बिहार विधान परिषद

(197वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

18 मार्च, 2021

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

Total Short Notice Question- 11

योजना स्थल पर स्थापित कब तक

*143 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **योजना एवं विकास** be pleased to state:-

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री ने 15 दिसम्बर, 2017 को विकास कार्य की समीक्षा यात्रा के क्रम में मधुबनी जिला मे करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह स्थल से ही रिमोट के माध्यम से किया था;

(ख) क्या यह सही है कि विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास से जुड़े शिलापट्ट संबंधित योजना स्थल पर न होकर दो वर्ष से जिला मुख्यालय स्थित विकास शाखा में पड़ा है;

(ग) क्या यह सही है कि संबंधित पदाधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता एवं असंवेदनशीलता के कारण ही योजनाओं से संबंधित शिलापट्ट को योजना स्थल पर दो वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं लगाया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिला की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास से जुड़े शिलापट्ट संबंधित योजना स्थल पर स्थापित कराना चाहती है ?

पेंशन भुगतान

***144 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

Will the **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** be pleased to state:-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्री अनिल कुमार सिंह (लिपिक) जिला कल्याण कार्यालय, जमुई से 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए और दो वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी तक मात्र अपुनरीक्षित दर पर सेवांत लाभ दिये गये और पेंशन भुगतान रोक रखा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार कर्मचारी नियंत्रण वर्गीकरण एवं अपील नियमावली के तृतीय वॉल्युम में निहित प्रावधान के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों का किसी भी प्रभाव से कोई भी वेतन वृद्धि रोका नहीं जाना है, किंतु इसकी अवहेलना कर जिला कल्याण पदाधिकारी, जमुई के द्वारा नियमों की अनदेखी कर दो वेतन वृद्धि रोकते हुए महालेखाकार कार्यालय में पेंशन प्रपत्र भेजे गये;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभागीय ACP / MACP जो 4800 ग्रेप पे में स्वीकृति किये गये हैं और महालेखाकार के द्वारा भी सभी उक्त लिपिकों को 4800 ग्रेड पे में पेंशन की स्वीकृति दी गई है उसके अनुरूप श्री अनिल कुमार को पेंशन भुगतान का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

अतिक्रमण मुक्त कब तक

***145 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **जल संसाधन** be pleased to state:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के उचकागांव के जमसड़ हाई स्कूल और जमसड़ से भुवला गांव तक जाने वाले पथ के बीच में गुजर रही गंडक नहर के उत्तर की पटरी पर अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि गांव के दक्षिण की तरफ घर से जाने में रास्ता अवरुद्ध हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नहर पर हुए अतिक्रमण को हटायेगी, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

दुर्घटनाओं से निजात कबतक

***146 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

Will the **परिवहन** be pleased to state:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में हर घंटा एक घंटा एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना से हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि सड़क दुर्घटना में 57 प्रतिशत लोगों की मौत एन.एच. पर होती है, और इस मौत के कारण सड़क का जाम होना और वाहनों को जलाया जाना आम बात हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस तरह की सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

इंद्रपुरी पनबिजली योजना

***147 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

Will the **जल संसाधन** be pleased to state:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार की सबसे बड़ी इंद्रपुरी पनबिजली परियोजना को बराज बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सही है कि बराज बनने के बाद आठ जिलों के किसानों को फायदा होगा, इससे करीब 190 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार को सोन नदी से 7.75 मिलियन एकड़ फुट (एमएएफ) पानी मिलना है, राज्य कैबिनेट ने डीपीआर बनाने की मंजूरी दी थी, केन्द्रीय जल आयोग को प्रारंभिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भेजी जा चुकी है

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जनहित में इंद्रपुरी पनबिजली परियोजना को बराज बनाना चाहती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***148 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

Will the **गृह** be pleased to state:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत बेलागंज प्रखंड की लक्ष्मीपुर पंचायत के शाह मोहम्मदपुर गांव में लगभग ढाई बिगहा (2.5) रकबा का कब्रिस्तान (खतियान क्रम सं.-117, खेसरा सं.-277) है;

(ख) क्या यह सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण इसका अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की प्राथमिकता के आधार पर घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

***149 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

Will the **जल संसाधन** be pleased to state:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा नगर परिषद् के रैयतों से ली गयी भूमि पर कटावरोधी कार्य करने के बाद भी मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि गंडक नदी के किनारे फेज एक एवं चार में कटावरोधी कार्य हेतु विभाग द्वारा रैयती भूमि ली गयी थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिम चम्पारण जिला की बगहा नगर परिषद् के रैयतों कोा के मुआवजा का भुगतान करना चाहेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नामांकन प्रक्रिया

***150 श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

Will the **श्रम संसाधन** be pleased to state:-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कुशल युवा कार्यक्रम संचालित करने वाले राज्य के लगभग 1700 केन्द्रों पर छात्रों का प्रशिक्षण कोरोना पैनडेमिक के उपरान्त 14 दिसम्बर, 2020 से प्रारंभ हो चुकी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रों पर छात्रों के नामांकन तिथि की घोषणा सरकार द्वारा नहीं किये जाने के कारण नामांकन प्रक्रिया रुकी हुई;

(ग) क्या यह सही है कि नामांकन प्रक्रिया नहीं होने से राज्य के अकुशल छात्रों का कौशल प्रशिक्षण बाधित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि कुशल युवा प्रशिक्षण केन्द्रों पर नामांकन प्रक्रिया कबतक शुरू करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

निजी क्षेत्र के बैंक

*151 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

Will the **वित्त विभाग** be pleased to state:-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में निजी क्षेत्र के अनेकों बैंक कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन बैंकों में राज्य की जनता का धन संग्रह होता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताना चाहेगी कि राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इन बैंकों का क्या योगदान है ?

उडाही का निर्माण

*152 **श्री खालिद अनवर (विधान सभा):**

Will the **जल संसाधन** be pleased to state:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में लाल बकियार नदी से ढाका नहर निकलती है, जिसकी उड़ाही पांच वर्षों से नहीं की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इन नदी के तटबंध पर पक्की सड़क नहीं रहने से आवागमन में एवं बराज का निर्माण नहीं होने से पटवन में कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ढाका नहर की उड़ाही, पक्की सड़क का निर्माण एवं बराज का निर्माण कबतक कराना चाहती है ?

आदेश रद्द करने पर विचार

*153 **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

Will the **परिवहन** be pleased to state:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भारत सरकार के केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 2019 की धारा एवं L.M.V.R. 1989 Rule 62 (1) के द्वारा I/C Centre Authorized में 18 बिन्दुओं पर जांच किये बगैर वाहनों का Fitness Certificate का नवीकरण नहीं किया जा सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली में वर्णित उपर्युक्त प्रावधानों का बिहार में अनुपालन नहीं किया जा रहा है, फलतः परिवहन वाहनों को दुरुस्तगी प्रमाण पत्र का नवीकरण एवं निर्गमन बगैर परीक्षण के ही निर्गत किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि विभागीय आदेश संख्या 730, दिनांक 06.02.2015 को रद्द करने से अविलम्ब 38 जांच केंन्द्र स्वतः कार्यरत हो जायेंगे;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य में वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, क्या सरकार उपर्युक्त कार्यों में लगे बेरोजगार अभियंताओं को रोजगार बहाल करने हेतु विभागीय आदेश संख्या 730, दिनांक 06.02.2015 को रद्द करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?